Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding development of canal and irrigation schemes and i ncrease in irregulation area in Rajasthan.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान के किसानों की एक महत्वपूर्ण मांग की तरफ जल शक्ति मंत्री और दिल्ली की सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए राजस्थान में सिंचित क्षेत्र विकसित करने व नहरी पानी की नवीन परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने व वर्तमान में विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार की मांग के क्रम में अवगत कराना चाहता हूं कि योजनाबद्ध विकास के 70 वर्षों से भी अधिक समय के बाद भी राजस्थान आधारभूत संरचना की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है ।

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और लोग जीवन स्तर के लिए कृषि पर निर्भर हैं, परन्तु भोगौलिक दृष्टि पर नज़र डाले तो अधिकतर खेती मानसून पर निर्भर है । कुल सिंचित क्षेत्र में 64 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र कुओं व नलकूपों पर निर्भर है, जबकि मात्र 33 प्रतिशत ही नहर से सिंचाई होती है, जो केवल जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर व हनुमानगढ़ तथा अल्प हिस्सा बाड़मेर जालोर व कोटा का भी है । इसलिए भारत सरकार यदि ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे तो पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर व धौलपुर आदि 13 जिलों में 26 बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत दो लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जा सकता है । यह बात सही है की राजस्थान मे सतत् प्रवाही नदियों के अभाव मे नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कम है, परन्तु भारत सरकार को नवीन योजनाएं बनाकर राजस्थान के किसानों के भले

के लिए सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग श्रीगंगानगर में, जबकि सबसे कम राजसमंद में है । वहीं कुल कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर में जबकि सबसे कम चुरू जिले में होती है ।

इसलिए उदाहरण के तौर पर बताऊं तो इंदिरा गांधी वृहद नहर परियोजना के अंतर्गत सिद्धमुख नोहर परियोजना का विस्तार किया जाए तो तारानगर, साहवा के साथ सुजानगढ़ क्षेत्र मे भी सिंचित क्षेत्र विकसित किया जा सकता है । इसके साथ ही बाढ़ के पानी को रोककर व पंजाब सहित अन्य राज्यों से पानी का जो हिस्सा बहकर पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोककर व आईजीएनपी का विस्तार करके नागौर, जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकता है । वहीं नर्मदा परियोजना का विस्तार करके बाड़मेर, जालौर में सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है । वहीं पंजाब हरियाणा आदि राज्यों से विभिन्न जल समझौते, जैसे रावी-व्यास जल समझौता सहित अन्य, का पूरा पानी राजस्थान को मिले तो उससे भी सिंचित क्षेत्र विकसित करने की पूर्ण संभावनाएँ बनती है । इसके साथ ही राजस्थान की नहर परियोजनाओ के विकास के लिए केंद्र को बजट जारी करने की ज़रूरत है । इसलिए सरकार किसान की पीड़ा को समझकर राजस्थान में नया सिंचित क्षेत्र विकसित करे । मैं आपके माध्यम से दिल्ली की सरकार का ध्यान और जल शक्ति मंत्री का ध्यान इस ओर आकृषित करना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाए ।